

स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान भरेगा उड़ान

एसएआईपीएल ने परियोजना के पहले चरण में 450 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की योजना बनाई

नई दिल्ली, 25 जनवरी. किसी निजी कंपनी द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान डायमंड डीए40 इस साल के अंत तक उड़ान भर सकता है. डीए40 विमानों की निर्माण शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएआईपीएल) कर रही है जो भारत के शक्ति समूह और ऑस्ट्रिया के डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का साझा उपक्रम है.

कंपनी ने मार्च 2025 में देश में इन विमानों की आपूर्ति शुरू की थी, लेकिन इनका भारत में निर्माण अभी नहीं हो रहा है. कंपनी ने ई-मेल पर भेजे गये सवालों के जवाब में यूनीवार्ता को



बताया कि वह तमिलनाडु के त्रिपुर में डीए40 विमानों के निर्माण के लिए एसंबली लाइन बना रही है. उत्पादन के लिए सभी उपकरण वहां पहुंच चुके हैं. इसे इस साल के मध्य तक नागर विमानन महानिदेशालय

(डीजीसीए) से सीएआर 21 प्रमाणन मिलने की उम्मीद है. इसके बाद अंतिम असेम्बली शुरू होगी.

कंपनी ने बताया कि वह इस साल की अंतिम तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान

इन विमानों की डिलिवरी शुरू करेगी. एसएआईपीएल ने परियोजना के पहले चरण में 450 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की योजना बनायी है. भारतीय कंपनियों की जरूरतें पूरी करने के अलावा कंपनी की योजना भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे देशों में भी डीए40 एनजी विमानों के निर्यात की है. कंपनी ने बताया है कि भविष्य में वह कलपुर्जों के निर्यात भी करेगी. डायमंड डीए40 एनजी चार सीट वाला सिंगल इंजन विमान है. कंपनी का कहना है कि देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र के साथ आने वाले समय में पायलट प्रशिक्षण के लिए विमानों की जरूरत भी बढ़ेगी.

देश में इस समय 35 उड़ान प्रशिक्षण संगठन हैं. सरकार की योजना अगले 10 साल में इसे दोगुना करने की है. इसे देखते हुए आने वाले समय में देश में प्रशिक्षण विमानों की मांग भी मजबूत बनी रहेगी. हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंस इंडिया 2026 के दौरान एसएआईपीएल अपने डीए40 एनजी, डीए42 और डीए 62 विमानों का प्रदर्शन करेगी. इन विमानों का उपयोग पायलट प्रशिक्षण के अलावा बहु-उद्देशीय अभियानों में भी किया जा सकता है.

आर्थिक कारकों से तय होगी बाजार की दिशा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व तथा वैश्विक कारकों का दिखेगा असर

मुंबई, 25 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही भारी गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेश धारणा पर आर्थिक सर्वेक्षण और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान जैसे बड़े घरेलू तथा वैश्विक कारकों का असर दिखेगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोपीय उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने से पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट रही. साथ ही डॉलर की तुलना में रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर तक लुढ़कने से भी निवेश धारणा कमजोर रही. वित्त वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को संसद में पेश किया जायेगा. औद्योगिक उत्पादन के दिसंबर के घरेलू आंकड़े भी इसी सप्ताह आने हैं.



गिरावट रही. रसायन और मीडिया समूहों के सूचकांक चार प्रतिशत से अधिक टूटे. वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य और तेल एवं गैस समूहों के सूचकांक तीन से चार प्रतिशत के बीच गिरे. ऑटो में 2.87 प्रतिशत, सार्वजनिक बैंकों में 2.53, निजी बैंकों में 2.40, फार्मा में 2.23 और आईटी में 2.17 प्रतिशत की गिरावट रही.

वैश्विक स्तर पर भू-राजनैतिक और व्यापार तनावों में प्रगति पर भी निवेशकों की नजर रहेगी. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 27-28 जनवरी को होने वाली है.

सप्ताह के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक

सेंसेक्स 2,032 अंक (2.43 प्रतिशत) लुढ़क गया और शुक्रवार को 81,537.70 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक 645.70 अंक यानी 2.51 प्रतिशत गिरकर सप्ताहांत पर 25,048.65 अंक पर बंद हुआ.

कोटक महिंद्रा बैंक को तीसरी तिमाही में 4,924 करोड़ का मुनाफा



हैदराबाद, 25 जनवरी. कोटक महिंद्रा बैंक को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में समेकित आधार पर 4,924 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जो सालाना आधार पर पांच प्रतिशत अधिक है.

बैंक के निदेशक मंडल की शनिवार को हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गयी. तिमाही के दौरान ब्याज से प्राप्त आय 17,507 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो सालाना आधार पर 5.25

प्रतिशत की वृद्धि है. वहीं, बैंक ने ग्राहकों को 7,384 करोड़ रुपये का ब्याज दिया. इस दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के मामले में बैंक का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. उसका सकल एनपीए एक साल पहले के 1.50 प्रतिशत से घटकर 1.30 प्रतिशत पर आ गया जबकि शुद्ध एनपीए 0.41 प्रतिशत से कम होकर 0.31 प्रतिशत पर रहा. आलोच्य तिमाही में बैंक द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4,80,673 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी. कुल औसत जमा भी 15 फीसदी बढ़कर 5,26,025 करोड़ रुपये रहा. चालू खाता जमा के औसत में 14 प्रतिशत और संचाधि जमा में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

एफपीआई निवेशकों ने जनवरी में निकाले 27,454 करोड़ रुपये

मुंबई, 25 जनवरी. देश के पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश (एफपीआई) में जनवरी में अबतक 27,454 करोड़ रुपये के गिरावट दर्ज की गयी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई निवेशकों ने जनवरी में शुद्ध रूप से 33,518 करोड़ रुपये की इकटिरी बेची. अन्य माध्यमों में वे शुद्ध रूप से लिवाल रहे हैं. शुद्ध बिकवाली का मतलब है कि उनकी बिक्री खरीद से अधिक रही. डेट में उन्होंने 5,538 करोड़ रुपये लगाये. हाइब्रिड माध्यमों में उनका निवेश 23.68 करोड़ रुपये रहा. म्यूचुअल फंड में उनका निवेश 626 करोड़ रुपये रहा. यह लगातार दूसरा महीना है जब एफपीआई निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं.

रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल मित्रा ऐप लॉन्च



तिरुवनंतपुरम, 25 जनवरी. केरल रेलवे पुलिस ने आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिये जनता को रेलवे पुलिस सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रेल मित्रा नामक एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है. यह एप्लिकेशन जन मैत्री सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

यह एप्लिकेशन जन मैत्री सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत शुरू इसका उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना

यह एप्लिकेशन जन मैत्री सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत शुरू इसका उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना

सेवाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए, रेल मित्रा को केरल पुलिस के आधिकारिक पीओएल-ऐप के साथ एकीकृत किया गया है. यात्री पीओएल -ऐप डाउनलोड करके रेल मित्रा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

वर्तमान में, केरल रेलवे पुलिस की पांच प्रमुख सेवाएं इस एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं. रेल मित्रा मोबाइल एप्लिकेशन का औपचारिक शुभारंभ थेकाउट पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में हुआ, जहां मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने एप्लिकेशन का उद्घाटन किया.

विझिंजम बंदरगाह के दूसरे चरण का काम शुरू

विकास के लिए होगा 10,000 करोड़ का निवेश

तिरुवनंतपुरम, 25 जनवरी. अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के दूसरे चरण के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल में शनिवार को एक कार्यक्रम में दूसरे चरण के विकास कार्य की औपचारिक



शुरूआत की. श्री विजयन ने कहा, विझिंजम बंदरगाह, जिसने भारतीय बंदरगाहों की सेवा करने वाले एक राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में बंदरगाह सेवा प्रदान करने वाला देश का सबसे तेज बंदरगाह बन गया है.

ट्रांसशिपमेंट का केंद्र बन जायेगा. विझिंजम अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बंदरगाहों की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनेगा. एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा कि यह परियोजना सहकारी संघवाद को साकार करने का एक सशक्त उदाहरण है. वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के केवल 15 महीने में ही यह 10 लाख टीईयू (20 फुट इक्विवैलेंट यूनिट) माल को बंदरगाह सेवा प्रदान करने वाला देश का सबसे तेज बंदरगाह बन गया है.

एनएमडीसी ने टोकीसुद नॉर्थ कोयला खदान में खनन किया शुरू

नई दिल्ली, 25 जनवरी. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित टोकीसुद नॉर्थ कोयला खदान में खनन शुरू कर दिया है. एनएमडीसी ने शुक्रवार को हुए इस उद्घाटन के साथ औपचारिक रूप से कोयला खनन क्षेत्र में कदम रखा है. कंपनी ने पहली बार लौह अयस्क से परे रणनीतिक विस्तार किया है, जिससे पूर्वी भारत में इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है.

नौ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटा

मुंबई, 25 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही जबरदस्त गिरावट के कारण बीएसई की शीर्ष 10 में शामिल नौ कंपनियों का समिलित बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 2,51,712 करोड़ रुपये घट गया.

सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 96,960 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का 48,645 करोड़ रुपये कम हुआ. हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 18,75,533 करोड़ रुपये के साथ अब भी शीर्ष पर है. एचडीएफसी



बैंक का एमकैप 22,923 करोड़ रुपये घटकर 14,09,612 करोड़ रुपये रहा गया. इस मामले में वह दूसरे स्थान पर बरकरार रही. भारती एयरटेल का एमकैप 17,534 करोड़ रुपये और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के एमकैप में 16,589 करोड़ रुपये की गिरावट रही. टीसीएस भी तीसरे स्थान पर कायम है.

समाचार विशेष

बिहार की राजनीति में हलचल

नीतीश के बेटे की एंट्री पर सबकी निगाहें

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की सक्रिय राजनीति में इंट्री और आरसीपी सिंह की जदयू में पुनर्वापसी की संभावना भी व्यक्त की जा रही थी. दोनों संभावनाओं पर जदयू में चर्चा शुरू हो गई है. इन संभावनाओं के जमीन पर उतरने के लिए केवल मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति की जरूरत है.

दोनों विषय कई बार उनके समक्ष रखे गए हैं. निशांत के मामले में दल के प्रायः सभी नेताओं ने नीतीश से आग्रह किया है. सामाजिक समारोहों में भी निशांत का जिनदाबाद किया जा रहा है. लेकिन, मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अपना मन नहीं बना पा रहे हैं. उनकी दुविधा परिवारवादी राजनीति के प्रति उनके अपने दृष्टिकोण के कारण है. वे राजनीति में परिवारवाद के विरोधी रहे हैं. हालांकि, उनके दल के कई विधायक और सांसद इसी परिवारवाद के दम पर डटे हुए हैं. जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष

आरसीपी सिंह की दल में पुनर्वापसी का मामला अब चर्चा के बदले धराताल पर आ गया है.पटेल छात्रावास में आयोजित दही-चूड़ा भोज के समय से शुरू हुई यह चर्चा अब मुख्यधारा में है. पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने आरसीपी की जदयू में इंट्री के प्रश्न को नकार कर इसे इंटरनेट मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना दिया है.

अतीत में जदयू में कौन आएगा? एक बार जाने के बाद आएगा कि नहीं आएगा? अतीत में इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की जवाबदेही नीतीश कुमार पर ही रही है. यहां तक कि तकनीकी तौर पर दल में रहते हुए नेतृत्व की कटु आलोचना के बाद भी सम्मानजनक वापसी का यहां उदाहरण है. अभी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद अरुण कुमार की पुनर्वापसी का तगड़ा विरोध हुआ था. वे पुत्र के जदयू में आए.

दोनों रहे हैं बेहद करीबी

कभी ललन सिंह और आरसीपी-दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं. साथ रहते समय इन दोनों की राय को नीतीश कुमार सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे हैं. आज भी ललन सिंह की राय को वीटो का दर्जा है. लेकिन, इंटरनेट मीडिया पर चल रही चर्चा में यह भी याद दिलाया जा रहा है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू की 115 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हुई थी, उस समय ललन सिंह अलगा रास्ते पर चल रहे थे. यही भूमिका 2025 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी की थी. 2015 में जदयू 115 से 71 पर आ गया था. उसके साल भर पहले के लोकसभा चुनाव में जदयू को केवल दो सीटें मिली थी. इन चुनावों में ललन सिंह और आरसीपी सक्रिय भूमिका में थे.

नितिन नबीन भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहेंगे

कार्यकाल खत्म होते लोकसभा चुनाव आने से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा!

नई दिल्ली. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी अपने पूर्ववर्ती जेपी नड्डा की तरह लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं. ध्यान रहे नड्डा को 2019 के जून में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद जनवरी 2020 में उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

उनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक था. भाजपा के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार दो बार अध्यक्ष रह सकता है. इस लिहाज से अगर भाजपा के दोनों शीर्ष नेता चाहते



तो नड्डा को तीन साल का एक और कार्यकाल दे सकते थे. अगर उनको दूसरा कार्यकाल नहीं देना था तो नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता था. यह भी ध्यान रखने की बात है कि जनवरी 2023 के आसपास कोई बड़ा चुनाव नहीं था. मई में सिर्फ कर्नाटक का

चुनाव होना था, जहां नड्डा की कोई खास भूमिका नहीं थी. कर्नाटक के रहने वाले बीएल संतोष उनकी टीम में संगठन महामंत्री थे. उनकी भूमिका थी, बीएस येदियुरप्पा की भूमिका थी और नरेंद्र मोदी व अमित शाह का रोल था. लेकिन जनवरी 2023 में जेपी नड्डा को विस्तार दिया गया. उसके बाद तो वे तीन साल तक सेवा विस्तार पर चले. आधिकारिक रूप से बिना दूसरा कार्यकाल हासिल किए वे तीन साल और अध्यक्ष रहे.

नितिन नबीन के लिए स्थितियां अलग हैं. उनका तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2029

बिहार चुनाव 2030 तक पद पर रहना तय

जाहिर है अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी बिहारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो उसका लाभ बिहार में लेने की कोशिश जरूर करेगी. यह इतिहास है कि आजादी के बाद से आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने बिहार के किसी नेता को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया था. सोचें, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े सजग और समझदार माने जाते हैं लेकिन कोई पार्टी उनको न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, न प्रधानमंत्री बनाती है, न गृह मंत्री बनाती है.

में पूरा होगा और उस समय लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी होगी.

डीएमके या टीवीके, किससे हाथ मिलाएंगी कांग्रेस?

चेन्नई. राजधानी नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ लंबी बैठकों के बाद तमिलनाडु कांग्रेस अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ सप्ताहांत में हुए विचार-विमर्श के बाद, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक बुलाई है.

हालांकि, इन तैयारियों के बीच पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसने राज्य में अपनी आगे की रणनीति स्पष्ट कर ली है? क्या कांग्रेस अपने पुराने और

मजबूत सहयोगी डीएमके के साथ ही बनी रहेगी, जिसने चुनाव जीतने के बाद सत्ता साझा करने से साफ मना कर दिया है, या फिर वह राज्य में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी 'टीवीके' के साथ मिलकर नए गठबंधन विकल्प तलाशेगी.

कांग्रेस-डीएमके गठबंधन टूटेगा? - तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन इस समय अपने सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है. खबरों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान ने राज्य इकाई को गठबंधन मर्यादा निर्धारण और पुराने सहयोगी के खिलाफ बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है.

गुटबाजी से ऊपर उठने की जरूरत

यह खींचतान ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी संता में है और कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी. लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते पार्टी न तो सरकार को प्रभावी ढंग से घेर पा रही है और न ही जनता के बीच कोई स्पष्ट संदेश दे पा रही है. यदि कांग्रेस को पंजाब में दोबारा राजनीतिक जमीन हासिल करनी है, तो उसे गुटबाजी से ऊपर उठकर सामूहिक नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति और संगठनात्मक अनुशासन पर जोर देना होगा.

